

संपादकीय  
सरकार पर दरोमदार

रिजर्व बैंक ने साल की आयिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरें घटाने से तो मना कर ही दिया, इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी पर ला दिया। इससे पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांच बार रीपोर्ट में कटौती की थी। रीपोर्ट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज केता है। जीडीपी ग्रोथ के ताजा अंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 4.5 फीसदी पर रिवासक आई है, जो पिछले छह साल का सबसे निचला स्तर है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजर्व बैंक रीपोर्ट में थोड़ी और कमी लाकर आर्थिक गतिविधियां तेज करने में सरकार का हाथ बंटा सकता है।

लेकिन एक तो पिछली पांच कर्टौतियां आर्थिक विकास के मोर्चे पर कुछ खास फायदा नहीं दे सकीं, दूसरे, लगातार कर्टौतियों के बाद अब रिजर्व बैंक के पास पीछे जाने की गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। खुदरा महंगाई दर का अनुमान उसने 4.7 से 5.1 प्रतिशत के बीच रखा है। ऐसे में रीपोर्ट को मौजूदा 5.15 प्रतिशत से नीचे लाना नकारात्मक ब्याज दरों के खतरनाक दराये में प्रवेश करने जैसा था। हालांकि आगे महंगाई नीचे जाने की स्थिति में आरबीआई ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। केंद्रीय बैंक ने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा पहले ही उठाए जा चुके कुछ कदमों के चलते अगली तिमाही में बेहतर नीति देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद व्य में आप ब्यौरे अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति की ओर ही इशारा करते हैं।

ग्रोथ रेट बेशक, इससे पहले भी पांच फीसदी से नीचे गई है। इस लिहाज से मौजूदा स्थितियों को अभूतपूर्व नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज कुछ उसी तरह की चुनौतियों का समाना कर रही है जो 21वीं सदी के इन दो दशकों में सबसे कठिन मानी जाती रही है। 2008-09 जैसी वैश्विक मंदी आज नहीं है और 2012-13 जैसी पौलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति भी नहीं है। लेकिन पिछले दोनों मौसों पर सरकारें संकट से निपटने के लिए हाथ-पांप मारती नजर आती थीं, जबकि इस बार सरकार की कोशिश संकट जैसी धारणा को ही सिरे से खारिज करने की रही है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी रिजर्व बैंक के इस बयान के बाद सारी जय-क्षय सरकार पर ही आ गई है।

ग्रोथ के चार प्रमुख कारकों में से तीन में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। न विदेशी निवेश की कोई लहर करीब है, न निजी निवेश में कोई उत्साह देखा जा रहा है, न ही उपभोक्ता खर्च में किसी बड़ी बढ़त के आसार हैं। ऐसे में सारी उम्मीदें सरकारी निवेश पर ही टिकी हैं। यह सरकार के कौशल का इकत्ताहन है। मिशनों की कोशिश छोटे-छोटे मामलों में भी आर्थिक सक्रियता की गुंजाइश बनाने की होनी चाहिए, ब्यान बहादुरी का बान जा चुका है। रिजर्व बैंक ने सुझाया है कि लिंबिट परियोजनाओं के रास्ते की अड्डें दूर करके इन्हें जल्द से जल्द चालू करना अभी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

&lt;/div